साइबर सुरक्षा के लिए जी-20 देश बनाएंगे वैश्विक नियंत्रण केंद्र

बढ़ते साइबर अपराध पर जताई चिंता, सूचना व तकनीक के आदान-प्रदान पर भी सहमति

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। जी-20 देशों के डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई। इस पर रोक के लिए सभी सदस्य देशों के बीच वैश्विक स्तर पर एक कॉमन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (नियंत्रण केंद्र) बनाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इसके तहत सदस्य देश एक दूसरे को साइबर व बायरस हमले की सूचना देने के साथ उससे बचाव के लिए भी सतर्क करेंगे।

राजधानी में जी-20 देशों की तीन दिनों तक चली बैठक के अंतिम दिन बुधवार को सामने आया कि डिजिटल इकॉनमी का प्रचलन बढ़ने के साथ साइबर अपराध भी बढ़ता जा रहा है। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने माना कि साइबर सुरक्षा पर बड़ा काम होना चाहिए। कहा गया कि कॉमन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाने से पता चल सकेगा कि साइबर अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र के संचालन के लिए देश आपसी सहयोग और समन्वय करेंगे। इससे डाटा लीकेज व साइबर धोखाधड़ी भी रुकेगी।

साइबर सुरक्षा पर बैठक को संबोधित करते केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश शर्मा व अपर सचिव भुवनेश कुमार। - संवाद

बैठक में साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि जी-20 सम्मेलन की मेजबानी के साथ ही भारत ने डिजिटल सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है।

- केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अलकेश शर्मा ने कहा कि सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने माना है कि जैसे-जैसे डिजिटलीकरण बढ़ेगा वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा। वर्किंग ग्रुप की आगामी तीन बैठकों में इस पर आगे की रणनीति बनेगी। साइबर सुरक्षा के अनुबंध पर आगामी बैठकों में निर्णय होगा।

प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण : साइबर अपराध रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भी जागरूक किया जाएगा।

आधार, डिजीलॉकर भी अपनाएंगे सदस्य देश

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत भारत में लागू आधार कार्ड, यूपीआई, डिजीलॉकर, ई-संजीवनी जैसे एप अपनाने पर सदस्य देश सहमत हुए। फिलिपींस ने आधार कार्ड, फ्रांस ने यूपीआई अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। कई देशों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग से बैठक करने पर बात की है।

- सदस्य देशों ने माना कि भारत में पिछले आठ वर्षों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्व में सबसे अधिक काम हुआ है। यह काम अपेक्षाकृत कम कीमत पर, पीपीपी मॉडल पर हुआ है। यदि किसी दूसरे देश में सामान्य गति से भी यह काम होते तो उसमें 40 वर्ष लग जाते।

डिजिटल कौशल तैयार करने के लिए बना रोडमैप... पेज 2 व माईसिटी